ऋण प्रदान किये जाने के संबंध में बैंक नियमों का उल्लंघन

1196. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक बिना प्रतिभूति के ऋण प्रदान नहीं कर रहे है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नियम हैं ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन नियमों के उल्लंघन के आरोप में कितने अधिकारियों को दंडित किया गया है; और

(घ) उनके खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सामान्यतया, बैंक उन्हें स्वीकार्य कुछ प्रतिभूतियों की एवज में ऋण प्रदान करते हैं जो संव्यवहारों के अन्तर्ग्रस्त जोखिम पर निर्भर करता है। बहरहाल, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अग्रिमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार लघु ऋणों के मामले में ऋणों से सृजित परिसंपत्तियों के गिरवी/दृष्टिबंधक/बंधक रखने को पर्याप्त प्रतिभूति समझा जाता है और बैंक 25,000/– रुपये तक के ऋणों के लिये संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पार्टी गारन्टी के लिये मांग नहीं करते हैं । 25,000/– रुपये से अधिक के ऋणों के लिये अचल संपत्तियों के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा अन्य पार्टी गारन्टी उन्हीं मामलों में मांगी जा सकती है जिनमें प्राथमिक प्रतिभूति अपर्याप्त हो या उसके लिये अन्य वैध कारण हो न कि एक सामान्य मामले के रूप में अन्यथा अर्थक्षम प्रस्तावों को केवल ऐसी सम्पार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पार्टी गारंटी न होने के कारण नामंजूर नहीं देना चाहिये ।

(ग) और (घ) आंकड़ा सूचना प्रणाली उन बैंक अधिकारियों की संख्या संबंधी सूचना नहीं देता है जिन्हें बैंक ऋणों के बदले प्रतिभूतियों के संबंध में नियमों के उल्लघंन के आरोपों में दंडित किया गया हो । बहरहाल, संबंधित बैंक के आंतरिक जांचकर्ताओं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के खातों की लेखा-परीक्षा और उनकी जांच के दौरान ऋण मूल्यांकन और अन्य मामलों के संबंध में बैंकों में विद्यमान विभिन्न कमियां पाई जाती है । सूचित किये गये उल्लंघनों से संबंधित मामलों में बैंकों द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

Man made Fibre Industry

@1197. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SABADA MOHANTY:
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether representations have been made by various sector of man made fibre industry about rationalisation of Customs and Excise duties of inputs that go into the production of these fibres/yarns;

(b) whether it is a fact that BICP has been asked to undertake a fresh cost stud!y of paraxylene, DMI, PTA, PSF and PIY;

(c) if so, how soon is BICP expected to complete the study and submit the report;

(d) whether Government have any plan to effect changes! in the Cust-oros/Excise tariffs pending receipt of BICP Report keeping in view the pressing needs of the market forces; and

(e) if not, the reasons therefor?

(^Previously Unstarred question 747, transferred from the 16th July, 1992.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESH WAR THAKUR): (a) Representations have been received from time to time from the Association of Polyster Staple Fibre Manufacturers requesting for reduction of import duty on paraxylene, PTA, DMT and MEG.

(b) Yes, Sir.

(c) BICP has taken up the stud^ and the time taken for its completion will depend to a large extent on the speed with which the manufacturers respond to the BICP's questionnaire seeking detailed information.

(d) and (e) Import duty on DMT, PTA and MEG was reduced from 150 per cent to 110 per cent in March, 1992. It is not possible to indicate at this stage whether any further change will be made before receipt of the BICP recommendations.

मध्य प्रदेश में मारे गये आयकर छापे

1198. **श्री अजीत जोगी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों के दौरान जब्त किये बिना हिसाब के कीमती सामान तथा नकदी का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक निपटाये गये मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या संबंधित व्यक्तियों के मामलों का निपटान करने के बाद उनसे जब्त किया गया कीमती सामान तथा नकदी उन्हें लौटा दी गई है ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं साथ ही ऐसे सामान का ब्यौरा क्या है जिसे अभी लौटाया जाना है ; और

(छ) देश के अन्य प्रदेशों में मारे गये ऐसे छापों की क्या स्थिति रही?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख)

(लाख रुपयों में)

वित्त वर्ष	तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत परिसंपत्तियों का मूल्य	छिपाई गई आय, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(4) के अन्तर्गत घोषित किया गया
1991-92	42	170.17	392.61
1990-91	163	508.14	248.52
1989-90	108	190.43	64.23